दिल्ली विद्युत बोर्ड में वितरण और पारगम्यता हानि

835. **श्री बरजिन्दर सिंह** :

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 3 फरवरी, 1998 के दैनिक "इकोनोमिक टाइम्स" में प्रकाशित "हाफ हाफ डी.वी.बीज पावर वेनिशेज इन टु थिन लेयर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि वितरण एवं पारगम्यता हानि जो 1992-93 मे 23% आंकी गई थी, वह 1996-97 में बढ़कर 50% हो गई है; और

(ग) यदि नहीं तो उपरोक्त दोनों वर्षो में दिल्ली राज्य में कितनी-कितनी बिजली उपलब्ध थी, तथा उक्त अवधि हेतु उपभोग की बिजली के लिए वर्ष-वार कितनी राशि के बिल तैयार किए गए ?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) से (ग) जी, हां । दिल्ली विद्युत बोर्ड

ने सूचित किया है कि पारेक्षण और वितरण हानि वर्ष 1992-93 के 23.98% में बढ़कर वर्ष 1996-97 में 49-85% हो गई है । इन्हीं वर्षो के दौरान विद्युत की उपलब्ध्ता 10,517 मिलियन यूनिट से बढ़कर 13,703 मिलियन यूनिट हो गई है और बिल की राशि 1072 करोड़ रुपये से बढ़कर 1782 करोड़ रुपये हो गई है ।

बांध के निर्माण के कारण गंगा में प्रदुषण

836. **श्री मनोहरकान्त ध्यानी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी में भागीरथि (गंगा) नदी पर बनने वाले हजारों करोड़ के बांध के निर्माण को लेकर विभिन्न कोणों से विरोध होता रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्व हिन्दू परिषद् ने इस जलाशय के निर्माण से गंगा की पवित्रता नष्ट होने की आशंका व्यक्त की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उनकी शंका के समाधान के क्या उपाय किए है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) पानी की गुणवत्ता के संबंध में रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा एक अध्ययन कार्य किया गया था । अध्ययन कार्य से पता लगा था कि पानी रोकने के कारण पानी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा । हनुमंताराव समिति जो परियोजना के पर्यावरणीय और पारस्थिति की पहलुओं का जांच कार्य कर रही है ने यह सिफारिश की थी कि जलाशय के डाउन स्ट्रीम पर पानी की गुणवत्ता पर सम्भावित संघानं की जांच के संबंध में अध्ययन कार्य किए जाने चाहिए । टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कारपोरेशन लि. को जल गुणवत्ता मानीटरिंग स्टेशन स्थापित करने की सलाह प्रदान की गई है ताकि जलाशय में पानी के गुणवत्ता की मानीटरिंग की जा सके । टीएचडीसी को डाउन स्ट्रीम जल की गुणवत्ता पर पड़ने वाले सम्भावित संघातं का मूल्यांकन करने हेतु अध्ययन कार्य करने की सलाह दी गई है यह उल्लेख किया जा सकता है कि जलाशय में पानी की कमी होने के कारण वर्षा की कमी तथा मानसून के जल का लगातार प्रवाह हो सकेगा । वर्षा की कमी के दौरान पानी छोड़े जाने से नदी में दौरान जल प्रवाह की स्थिति में सुधार आयेगा ।

टिहरी बांध का निर्माण पूरा होना

837. **श्री मनोहरकान्त ध्यानी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टिहरी बांध पर अब तक ऐसे बांधों की तुलना में कई गुना अधिक राशि लगने के बावजूद भी इसका निर्माण कार्य कई वर्ष पीछे चल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में आने वाले टिहरी नगर एवं आस-पास के पूर्णतया डूब जाने तथा आंशिक रुप से डूब जाने की आंशका वाले क्षेत्र में आने वाले ग्रामों का पुनर्वास अभी तक नहीं हो पाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कब तक सभी लोगों का पुनर्वास किए जाने का विचार है तथा इसमें राज्य सरकार की क्या भूमिका है; और

(घ) क्या यह सच है कि यहां के मूल निवासियों के अलावा बहुत से अनधिकृत व्यक्तियों को नई टिहरी में प्लाट आबंटित किए गए है ?

विद्युत मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) टिहरी बांध और जल विद्युत परियोजना को मूलतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य क्षेत्र के तौर पर निष्पादित किए जाने के लिए अनुमोदित किया गया था । इस परियोजना की लागत 1370.86 करोड़ रुपये (1987 के मूल्य स्तर पर) थी । वर्ष 1989 में इसके राज्य सरकार से टिहरी जल विद्युत विकास निगम को अंतरित किए जाने के पश्चात् 1000 मे.वा. की अधिष्ठापित क्षमता के साथ जल विद्युत परियोजना चरण-। और टिहरी बांध का अनुमोदन 2815 करोड़ रुपये (मार्च, 1993 के मूल्य स्तर पर) की